भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 197

उत्तर देने की तारीख: 18.07.2022

एनईपी, 2020 में सार्वजनिक परामर्श का सूत्रीकरण

†197. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **क्या नीति संबंधी इतिहास के सबसे बड़े सार्वजनिक परामर्श के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)**, 2020 **तैयार की गई थी**;

(ख) **यदि हां**, **तो क्या व्यापक विचार विमर्श और सामूहिक योगदान के बावजूद**, **नीति में परिणामों की स्पष्ट अभिव्यक्ति और नीति के विकास का अभाव है**;

(ग) **यदि हां**, **तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**; **और**

(घ) **इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है**?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) **से** (घ): **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** 2020 **को सभी हितधारकों को शामिल करते हुए ऑनलाइन, बुनियादी स्तर पर और विषयगत विशेषज्ञ परामर्श के माध्यम से उच्च स्तर की सहभागिता, समावेशी और बहुआयामी परामर्श प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप दिया गया है। विभिन्न हितधारकों अर्थात राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों, संसद सदस्यों, शैक्षिक संस्थानों, उद्योगों, जन-समुदाय आदि के साथ अत्यधिक परामर्श/विचार-विमर्श किया गया था।**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (**एनईपी** 2020) **कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समयसीमा के साथ-साथ सिद्धांत और कार्यप्रणाली प्रदान करती है। एनईपी 2020 के अनुसार, नीति के कार्यान्वयन के लिए कई पहलों और कार्यों की आवश्यकता है, जिन्हें विविध निकायों द्वारा सुचारु रूप से और व्यवस्थित ढंग से करना होगा। चूंकि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच सावधानीपूर्वक आयोजना तैयार करने, संयुक्त निगरानी और सहयोगात्मक कार्यान्वयन की आवश्यकता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।**

एनईपी कार्यान्वयन के लिए नवाचारी सोच पर चर्चा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के साथ समय-समय पर कार्यशालाओं/सेमिनारों/बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है। इस दिशा में, हाल ही में 15 से 17 जून 2022 तक मुख्य सचिवों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई थी। साथ ही, उच्चतर शिक्षा के लिए एनईपी 2020 के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए 7 से 9 जुलाई 2022 तक एक अखिल भारतीय शिक्षा समागम भी आयोजित किया गया था। इस समागम में केंद्रीय/राज्य/समवत/निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशकों/प्रमुखों, कॉलेजों के प्रधानाचार्यों/संकायों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं आदि ने भाग लिया।

****